



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54171

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2669/2026

रमापति

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : बलराम जी वर्मा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 39

(क्रम संख्या 22)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने लिखित निर्देश दिए हैं जो रिकॉर्ड पर लिए गए हैं।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम जी वर्मा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर मिश्रा को सुना।
3. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई है, जिसमें दिनांक 09.12.2025 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके पति- स्वर्गीय राम दुलारे यादव के वेतन के गलत निर्धारण के कारण 4,78,991/- रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में सेक्शन मिस्त्री के रूप में काम कर रहा था।
3. प्रकरण के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पति स्वर्गीय राम दुलारे सिंचाई विभाग में अनुभाग मिस्त्री के रूप में कार्यरत थे। वह 31.08.2016 को सेवानिवृत्त हुए। 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर, प्रत्यर्थीगण द्वारा उनकी पेंशन आदि की पुनर्गणना और भुगतान किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता के पति की 24.04.2025 को मृत्यु हो गई है। याचिकाकर्ता के पति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की मृत्यु के बाद, दिनांक 09.12.2025 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थीगण ने पेंशन की राशि के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक वसूली नोटिस जारी किया, जिसकी गणना याचिकाकर्ता के पति के पक्ष में गलत तरीके से की गई थी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह, 2015 (4) एससीसी 334** में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई वसूली शुरू नहीं की जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता का पति सिंचाई विभाग में ग्रुप-डी का कर्मचारी था और वेतन/पेंशन के निर्धारण या गणना में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। याचिकाकर्ता के पति ने संबंधित समय पर याचिकाकर्ता के पति को और न ही याचिकाकर्ता के पति को वेतन/पेंशन के इस तरह के निर्धारण/गणना के समय कोई पूर्व वचन पत्र नहीं लिया था।

5. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता याचिकाकर्ता के पति द्वारा 17.11.2023 को दिए गए वचन पर भरोसा करते हैं, जिसके तहत वह बकाया राशि, यदि कोई हो, जमा करने के लिए सहमत हो गया है, जो याचिकाकर्ता के पति को गलत तरीके से भुगतान किया गया है और इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि चूंकि याचिकाकर्ता के पति द्वारा एक वचन दिया गया था, इसलिए **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम जगदेव सिंह (2016) 14 एससीसी 267** में फैसले के संदर्भ में वसूली उचित है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने प्रकरण के रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है। रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का पति 31.08.2016 को सेवानिवृत्त हो गया है और उसके बाद 7 वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद, उसके वेतन/पेंशन की पुनर्गणना की गई थी। प्रत्यर्थीगण का यह मामला है कि इसकी गलत गणना की गई है और याचिकाकर्ता के पति को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है। रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है कि इस तरह के पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना के समय याचिकाकर्ता के पति से कभी भी कोई वचन नहीं लिया गया था। बल्कि बाद के किसी चरण में 17.11.2023 को याचिकाकर्ता के पति से कथित तौर पर कुछ वचन पत्र लिया गया है। याचिकाकर्ता के पति की भी अप्रैल 2025 में मृत्यु हो गई है और उसके बाद दिसंबर 2025 में प्रत्यर्थीगण द्वारा तत्काल वसूली आदेश पारित किया गया है। **रफीक मसीह (पूर्वोक्त)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"12. कठिनाई की सभी स्थितियों को मानना संभव नहीं है, जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से भुगतान किया गया है, उनकी पात्रता से अधिक। जैसा कि हो सकता है, ऊपर दिए गए निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली, कानून में अनुमेय होगी:

- (i) कक्षा III और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह C और समूह D सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
- (ii) (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या कर्मचारियों से वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से वसूली।
- (iii) (iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।
- (iv) (iv) उन मामलों में वसूली जहां एक कर्मचारी को गलत तरीके से एक उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है, और तदनुसार भुगतान किया गया है, भले ही उसे एक अवर पद के खिलाफ काम करने के लिए सही रूप से आवश्यक होना चाहिए था।
- (v) (v) किसी अन्य प्रकरण में, जहां न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि वसूली यदि कर्मचारी से की जाती है, इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगा, जैसा कि नियोक्ता के पुनर्प्राप्त करने के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगा।

7. जगदेव सिंह (पूर्वोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"11. उपरोक्त प्रस्ताव (ii) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण जैसी स्थिति पर लागू नहीं हो सकता है। वर्तमान प्रकरण में, जिस अधिकारी को पहली बार में भुगतान किया गया था, उसे स्पष्ट रूप से नोटिस पर रखा गया था कि अधिक भुगतान किए गए पाए जाने पर उसे वापस करने की आवश्यकता होगी। अधिकारी ने संशोधित वेतनमान का चयन करते समय एक हलफनामा प्रस्तुत किया। वह अंडरटेकिंग से बंधा हुआ है।

8. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का पति स्वीकार किया जाता है कि ग्रुप-डी का कर्मचारी था और याचिकाकर्ता के पति को वेतन/पेंशन के निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसलिए, **रफीक मसीह (पूर्वोक्त)** के फैसले के संदर्भ में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई वसूली शुरू नहीं की जा सकती है। जहां तक वचन पत्र का संबंध है, इसे वेतन/पेंशन के पुनर्निर्धारण के समय लिया जाना चाहिए। हालांकि, कोई भी बाद का उपक्रम कर्मचारी को बाध्य नहीं करेगा और प्रत्यर्थीगण को उक्त राशि की वसूली के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा गलती से गलत गणना के कारण गलत तरीके से भुगतान किया गया है।

9. प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका **स्वीकृत** की जाती है और वसूली आदेश दिनांक 09.12.2025 को रद्द कर दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

17 मार्च, 2026

आशीष पीडी.